1	2	3	4
37	12-12-92	8.55	8.46
38	19-12-92	8.55	8.64
39	26-12-92	7.84	
40	02-01-93	7.12	
41	09-01-93	6.97	
42	16-01-93	6.77	
43	23-01-93	7.00	
44	30-01-93	6.86	
45	06-02-93	6.95	
46	13-02-93	6.56	

* The index at the time of its release is provisional and it is made final after eight weeks by which time the required information is available.

Objective of LERMS

895. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the main objective behind the introduction of Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS);

(b) what is the extent to which Government succeeded in achieving the objective;

(c) whether there is any failure in achieving the objective; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The introduction of the Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) effective from 1st March, 1992, is aimed at eliminating licensing control and allowing the exchange rate to reflect the scarcity of foreign exchange. The system has worked fairly well so far. Despite virtually complete removal of import licensing on all raw materials components, intermediates and capital goods, the trade account has been managed fairly effectively without any undue pressure on the exchange rate. The difference between free market rate and the illegal or hawala rate is fairly small, around eight per cent or so, which is an important factor moderating the diversion of foreign exchange into illegal channels.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Impact of new financial measures on NRI Investment

896. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) What has been the Impact of new Financial Measures on the investment made by NRIs; and

(b) what are the results of the periodic studies conducted on the investment made by NRIs and MNCs after the announcement of new policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) The investment proposals received from NRIs and appro-

ved during the period 1990—92 are as follows:—

Year	(Rs. in Millions)
1990	52.40
1991	197.00
1992	4391.30

(b) The investment response as reflected in the approvals given during the years 1990—92 for foreign investments shows a significant increase. The figures for the years 1990, 1991 and 1992 are Rs. 1283.20, Rs. 5341 10 and Rs. 38875.40 millions respectively. No formal study has, however, been undertaken so far by the Government on foreign investments and NRI investments.

उत्तर प्रदेश के बड़े कृषकों को बैंकों से दिये गये ऋण

897. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उत्तर प्रदेश की बड़ी-बड़ी नदियों के किनारों पर रहने वाले किसानों को पाइप लाइन बिछाने और बिजली की मोटरें लगाने के लिये 50 हजार से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार इन किसानों के ऋणों को माफ करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इन पाइप लाइनों पर 50 प्रतिशत राज सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गये ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। अलबत्ता, जून 1990–91 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, लघु सिंचाई योजना के लिये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि भी लगभग 3 लाख खातों में 225 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऋणों को सपाट रूप से बट्टे खाते डालने के हक में नहीं हैं। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने किन्हीं वर्गों के पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/– रुपये प्रति उधारकर्ता ऋण राहत प्रदान करने के लिये मई, 1990 में एक योजना तैयार की थी। यह योजना पहले ही 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है।

(घ) पाइप लाइन आदि बिछाने के लिये बताई गई सब्सिडी प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार की किसी योजना की जानकारी नाबार्ड के पास नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुये प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश को अनुदान राशि/ऋण राशि में कमी

898. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 और विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को दी गई वार्षिक अनुदान राशि और लघु अवधि ऋण राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को दी गई वार्षिक अनुदान राशि और लघु अवधि ऋण राशि में कमी हुई है